भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 39
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
31 आषाढ़, 1946 (शक)

ओडिशा में खेल अवसंरचना का विकास

39. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा में खेल अवसंरचना के विकास के लिए धनराशि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क् या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार की विद्यालयों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : जी हां । विगत पाँच वर्षों के दौरान, ओडिशा राज्य में खेल अवसंरचना के विकास के लिए धनराशि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार से सात प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में से खेलो इंडिया स्कीम के तहत प्राप्त रायरंगपुर, जिला मयूरभंज, ओडिशा में खेल परिसर के निर्माण की परियोजना के प्रस्ताव को 27.23 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, ओडिशा को खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है जिसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय बच्चों को कक्षा VI से XII तक उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत, 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले ब्लॉक (जनगणना 2011 के अनुसार) में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाना है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी छात्रों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने ईएमआरएस में 15 खेल उत्कृष्टता केंद्र (एसटीसी) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत स्कूलों में खेल, शारीरिक गतिविधियों, योग, सह-पाठयक्रम गतिविधियों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा घटक की शुरुआत की गई है। सरकारी स्कूलों के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये और माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये तक की वार्षिक दर से खेल उपकरणों के लिए अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के तहत 812.42 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता के रूप में सभी सरकारी स्कूलों को वार्षिक आधार पर समग्र विद्यालयी अनुदान स्वीकृत किया जाता है। यह धनराशि गैर-कार्यात्मक विद्यालयी उपकरणों की खरीद और खेल के मैदान, खेल के उपकरण, इनडोर गतिविधियों आदि के रख-रखाव सहित अन्य आवर्ती लागतों को वहन करने के लिए प्रदान की जाती है।

****